

देश में घटी एलपीजी की खपत



नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 04 सितंबर भारत में घरेलू और अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी पानी रईस की खपत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच देश में एलपीजी की खपत करीब 16 फीसदी घटकर 11.3 मिलियन टन रह गई.

पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 13.4 मिलियन टन था. तेल मंत्रालय के

ईरान संकट के बीच बदली तस्वीर, पीएनजी की ओर बढ़ रहे लोग

पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के डेटा के मुताबिक, एलपीजी की खपत में यह कमी ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध के कारण एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा है. इसके साथ ही सरकार अब ज्यादा से ज्यादा घरों को पीएनजी पानी जरिए मिलने वाली प्राकृतिक गैस से जोड़ने पर जोर दे रही है. के

पिछले माह पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ी अगस्त में भी एलजी की खरीद हुई अगस्त 2025 में 29 मिलियन टन एलपी इस्तेमाल हुई थी, वहीं अगस्त 2006 में यह घटकर 2.4 मिलियन टन रह गई औरत की खब की खपत 6.4 फीसदी

एलपीजी की मांग में कमी केवल आपूर्ति संबंधी दबाव का नतीजा नहीं है, बल्कि प्राकृतिक गैस की ओर बढ़ते रुझान और ऊर्जा उपयोग के बदलते तौर-तरीकों का भी असर दिखाई दे रहा है. पश्चिम एशिया के तनाव के बीच ईंधन आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितता ने सरकार और ऊर्जा कंपनियों के सामने वैकल्पिक व्यवस्था मजबूत करने की चुनौती भी बढ़ा दी है. आने वाले महीनों में एलपीजी की उपलब्धता, कोमलता और पीएनजी कनेक्शन के विस्तार पर नजर रहेगी, क्योंकि इनका सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की ईंधन जरूरतों पर पड़ सकता है .

बढ़कर 18.9 मिलियन टन हो गई. की बढ़कर 40.5 मिलियन ट सही. अगस्त में पेट्रोल की खपत 7.9 फीसदी बढ़कर 3.8 मिलियन टन और 6.4 के मुताबिक बारिश के पेटेंट में बला के कारण कई इलाकों लिए जा रहा था देश में एलपीजी की खपत में आई तेज गिरावट ने ऊर्जा इस्तेमाल के

बदलते रुझान की तस्वीर सामने रखी है. अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच भारत में घरेलू और अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की खपत करीब 16 फीसदी घटकर 11.3 मिलियन टन रह गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 13.4 मिलियन टन थी.

इंसानों जैसी सोच वाला एआई, नए मॉडल ने मचाई हलचल

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 4 सितंबर. कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में नए मॉडल को लेकर हलचल तेज हो गई है. दावा है कि यह मॉडल केवल सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कंप्यूटर पर कई जटिल काम खुद पूरा कर सकेगा. वेबसाइट बनाना, कोड तैयार करना, खेल विकसित करना और साइबर सुरक्षा से जुड़े कार्यों को संभालना इसकी प्रमुख क्षमताओं में शामिल बताए जा रहे हैं. नया मॉडल कंप्यूटर आधारित कामों को पुराने मॉडल की तुलना में अधिक तेजी से पूरा कर सकता है. एक उदाहरण में दावा किया गया जिस मकान की तलाश में ईसान को करीब छह घंटे लग सकते हैं, उसे इस मॉडल ने दस मिनट से भी कम समय में पूरा किया.

96 प्रतिशत कारोबार रुपया-रुबल में

► यूएस-चीन दंग भारत-रूस ने किया कपाल

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 04 सितंबर रूस-भारत कारोबार की रुपया-रुबल से बढ़ावा मिला है और 96% लेन-देन में इन दोनों मुद्राओं में हो रहे हैं. रूस और भारत ने रुपया और रुबल का इस्तेमाल करके भुगतान का एक कारगर सिस्टम बनाया है, जिसके जरिए अब दोनों देशों के बीच 96% कारोबार का सेटलमेंट इन्हीं करेंसी में होता है.

2024 में रूस और भारत के बीच व्यापार रिकॉर्ड 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया. यह 2022 में यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद से तीन गुना हो गया है. इसकी एक खास वजह है. दरअसल भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण सस्ते



मिल रहे रूसी तेल का आयात बढ़ा दिया. 2025 में जब ये प्रतिबंध और कड़े किए गए तो दोनों देशों के बीच व्यापार में गिरावट आई, लेकिन 2026 की पहली छमाही में इसमें

फिर से तेजी आई.

रूसी कंपनियों को थी शिकायत- रूसी कंपनियों ने पहले द्विपक्षीय लेन-देन में रुपये (जो पूरी तरह से कन्वर्टिबल करेंसी नहीं है) के जमा होने और ट्रेड असंतुलन की शिकायत की थी, क्योंकि रूसी तेल के बढ़ते आयात के मुकाबले रूस को भारत का निर्यात कम था. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अभी 22 रूसी बैंक और 17 भारतीय बैंक द्विपक्षीय व्यापार में सेवाएं दे रहे हैं.

ट्रांजेक्शन एक मिनट से भी कम समय में हो रहे पूरे

अनुसार रूस और भारत के बीच 90% ट्रांजेक्शन 10 मिनट के अंदर पूरे हो जाते हैं, जबकि 50% से ज्यादा ट्रांजेक्शन एक मिनट से भी कम समय में पूरे हो जाते हैं. बीते सोमवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ बढ़ते आर्थिक संबंधों की तारीफ की. दोनों देशों के बीच 2030 तक 100 अरब डॉलर का ट्रेड पहुंच सकता है.

15 सितंबर से दुकानदारों का यूपीआई हो सकता है बंद

► पेमेंट कंपनियों ने आरबीआई से डेडलाइन बढ़ाने की अपील की

► लाखों दुकानदारों का अब तक पूरा नहीं हुआ वैरिफिकेशन

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 4 सितंबर देशभर के लाखों छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे ऑनलाइन कारोबारियों के सामने डिजिटल पेमेंट को लेकर संकट खड़ा हो सकता है. पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से मर्चेन्ट्स की री-केवाईसी पूरी करने की 15 सितंबर की तय समयसीमा बढ़ाने की मांग की है. कंपनियों का कहना है कि

बड़ी संख्या में दुकानदारों का वेरिफिकेशन अभी बाकी है और निर्धारित समय में पूरी प्रक्रिया खत्म करना मुश्किल है. री-केवाईसी पूरी नहीं होने की स्थिति में संबंधित मर्चेंट अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे दुकानदारों के लिए यूपीआई और अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना प्रभावित हो सकता है. इसका सीधा असर उन छोटे कारोबारियों पर पड़ने की आशंका है, जो रोजाना लेन-देन के लिए क्यूआर कोड और साउंड बैंक्स जैसी डिजिटल भुगतान सुविधाओं पर निर्भर हैं. करीब 10 लाख छोटे ऑनलाइन कारोबारियों पर इसका असर पड़ सकता है.

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में जियो के 10 साल बेमिसाल

नवभारत कनेक्ट

रायपुर, 4 सितंबर दस साल पहले मोबाइल हाथ में था, लेकिन इंटरनेट की रफ्तार और पहुंच आज जैसी नहीं थी। महंगा डेटा और सीमित कनेक्टिविटी

► 5.09 करोड़ तक पहुंचा ग्राहक आधार

► 58.4 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी

डिजिटल दुनिया की राह में बड़ी बाधा थे।

वर्ष 2016 में रिलायंस जियो के आगमन के बाद देश के दूरसंचार परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया। मोबाइल इंटरनेट सुविधा से आगे बढ़कर रोजमर्रा की जरूरत बन गया। मध्यप्रदेश और

छत्तीसगढ़ भी इस डिजिटल बदलाव के प्रमुख हिस्सेदार बने। सितंबर 2016 में सेवा शुरू होने के समय मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में जियो के महज 8.9 लाख ग्राहक थे। जुलाई 2026 तक यह संख्या बढ़कर करीब 5.09 करोड़ हो गई। यानी करीब एक दशक में कंपनी का ग्राहक आधार 56.6 गुना बढ़ा। जुलाई 2026 तक मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्किल में कुल 8.71 करोड़ मोबाइल कनेक्शन** हैं। इनमें जियो की हिस्सेदारी 58.4 प्रतिशत पहुंच चुकी है। अगस्त 2018 में एयरटेल और अक्टूबर 2019 में वोडाफोन आइडिया को पीछे छोड़कर नंबर-1 बनने के बाद जियो ने यह स्थान लगातार बनाए रखा है।

मस्क की दौलत में 54.2 अरब डॉलर का उछाल

स्पेसएक्स और टेस्ला के शेयर चढ़े, 922 अरब डॉलर हुई संपत्ति

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 4 सितंबर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की संपत्ति में एक ही दिन में 54.2 अरब डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है. स्पेसएक्स और टेस्ला के शेयरों में जोरदार तेजी के बाद मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर 922 अरब डॉलर हो गई.

ब्लूमबर्ग अरबपति सूचकांक के मुताबिक अब मस्क खरबपति बनने की दौड़ में केवल 78 अरब डॉलर दूर हैं. शेयर बाजार में तेजी



के साथ उनकी संपत्ति में यह उछाल आया है.

स्पेसएक्स के शेयर में गुरुवार, 3 सितंबर को 6.42 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और इसका भाव 149.74 डॉलर तक पहुंच गया. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी

टेस्ला के शेयर में भी 5.42 प्रतिशत की बढ़त रही और यह 376.36 डॉलर पर बंद हुआ. दोनों कंपनियों में मस्क की बड़ी हिस्सेदारी होने के कारण शेयरों की तेजी का सीधा असर उनकी कुल संपत्ति पर पड़ा.

इससे पहले स्पेसएक्स के शेयरों में गिरावट के कारण मस्क की संपत्ति में कमी आई थी. हालांकि, यह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे. अब शेयरों में ताजा उछाल ने उन्हें फिर से खरबपति बनने के करीब पहुंचा दिया है.

वाई-वाई नूडल्स बनाने वाली कंपनी पर एफएसएसएआई की कार्रवाई

नवभारत न्यूज नेटवर्क अजमेर, 4 सितंबर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सीजी फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अजमेर स्थित रूपनगढ़ संयंत्र में निरीक्षण के बाद कार्रवाई की है.

एफएसएसएआई ने कंपनी को आवश्यक मंजूरी और सुरक्षा उपायों के बिना वेज भुजिया नमकीन का उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया है. निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, लाइसेंस और



पैकेजिंग से जुड़े कई उल्लंघन सामने आने की बात प्राधिकरण ने कही है. एफएसएसएआई के अनुसार, संयंत्र में फर्श से एकत्र किए गए टूटे हुए नूडल्स को बिना उचित ताप उपचार के भुजिया उत्पादों में दोबारा इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई.

एयरटेल द टीचर ऐप के 3 लाख उपयोगकर्ता

नवभारत कनेक्ट नई दिल्ली, 4 सितंबर शिक्षक दिवस से पहले भारती एयरटेल फाउंडेशन ने अपने आजीवन

चार राज्यों और 12 आकांक्षी जिलों में साझेदारी 25 वर्षों में 43 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच

नि:शुल्क डिजिटल मंच द टीचर ऐप के देशभर में करीब तीन लाख उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने की घोषणा की है। नवंबर 2024 में शुरू किए गए इस मंच का उद्देश्य



शिक्षकों को निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए सीखने की सामग्री, कक्षा-केंद्रित उपकरण और सहयोगी समुदाय एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। यह मंच राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शिक्षकों को बदलती शैक्षणिक जरूरतों के लिए तैयार करने पर केंद्रित है।

फाउंडेशन के अनुसार द टीचर ऐप अब 36 राज्यों और

केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षक-विकास को बढ़ावा दे रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड की सरकारों के साथ राज्य स्तरीय सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों के लिए साझेदारी की गई है। मंच पर चार हजार घंटे से अधिक सीखने की सामग्री और 45 से ज्यादा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण उपकरण उपलब्ध हैं।

नीति आयोग के सहयोग से आकांक्षी जिलों में आधारभूत साक्षरता, डिजिटल तत्परता और कक्षा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।

समाचार विशेष

दीपेंद्र हुड्डा का मामला पीछे हो गया

नई दिल्ली, 4 सितंबर. भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान को बड़ा मुद्दा बनाया था, जो उन्होंने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के निधन पर दिया था.

दीपेंद्र ने स'जन कुमार के निधन को अपूरणीय क्षति करार दिया था. इसके बाद भाजपा उनके ऊपर हमलावर थी और अकाली दल ने तो मोर्चा ही खोला था. लेकिन अब वह मामला दब गया है क्योंकि दिल्ली के तीन भाजपा सांसद उनसे आगे बढ़ कर स'जन कुमार की शोक सभा में चले गए. दिल्ली के सांसद

रामवीर सिंह विधुड़ी, कमलजीत सहरावत और योगेंद्र चंदोलिया तीनों सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए.

गौरतलब है स'जन कुमार दिल्ली के सिख विरोधी दंगों से जुड़े



एक मामले में सजा पा चुके हैं और अन्य मामलों में आरोपी हैं. तभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीनों नेताओं को डांट लगाई. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं

पड़ता है. तीनों को पता है कि दिल्ली में उनकी राजनीति के लिए जाट वोट का कितना महत्व है.

मोदी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी ...

गडकरी का बदलेगा मंत्रालय! महाराष्ट्र से किसे मिलेगी जगह ?

नई दिल्ली, 4 सितंबर. क्या देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता के गलियारों में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? क्या देश के सबसे चर्चित मंत्रालयों के नेतृत्व में कोई ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी? जी हां, इस समय मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द ही एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसमें कई पुराने मंत्रियों को छुड़ी दी जा सकती है



और नए व युवा चेहरों को देश की कमान संभालने का मौका मिल सकता है. इस संभावित बदलाव की सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का विभाग बदला जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी कैबिनेट विस्तार में कई



चौंकाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं. जहां शानदार परफॉर्मंस देने वाले केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव को प्रमोशन मिल सकता है, वहीं नितिन गडकरी के पास मौजूद मौजूदा विभाग को बदलकर उन्हें कोई दूसरा मंत्रालय सौंपा जा सकता है.

योगी के साथ स्मृति का डबल इंजन प्लान!



लखनऊ, 4 सितंबर. यूपी चुनाव 2027 की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है. सपा और बीजेपी में आने वाले दिनों में यूपी में महासंग्राम शुरू होने वाला है. इसकी सुगबुगाहट बीते दिनों



बीजेपी की नई टीम के ऐलान के बाद देखने को मिली, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी.

लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी से

मिली अप्रत्याशित हार के बाद स्मृति ईरानी यूपी से दूर चली गई थीं, लेकिन महासचिव बनने के बाद यूपी के मैदान में दोबारा बड़ी सक्रियता और उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट्स यह साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी 2027 के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है. सवाल उठ रहा है कि क्या स्मृति ईरानी का यूपी में एक्टिव होना बीजेपी के लिए फायदों का सौदा होगा या कोई नुकसान? क्या बीजेपी उनके जरिए उत्तर प्रदेश की विशाल महिला वोटर्स को सीधे अपने पाले में करने की तैयारी में है?

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद स्मृति ईरानी ने उत्तर प्रदेश

और खासकर अमेठी से अपना नाता नहीं तोड़ा है. उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट्सए सार्वजनिक कार्यक्रमों की तस्वीरें और ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं से संवाद इस बात के गवाह हैं. भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और रा'य स्तर के संगठनात्मक ढांचे में स्मृति ईरानी का नाम एक बार फिर से केंद्र में आ गया है, जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है.

क्या 2027 में टूट कार्ड बनेंगी स्मृति?– राष्ट्रीय राजनीति में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, जेन-जी आंदोलन के बाद बदले हुए हालात में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी है.

फायदे और नुकसान

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यूपी चुनाव 2027 में एक स्टार महिला प्रचारक की कमी को स्मृति ईरानी पूरा कर देंगी. यूपी बीजेपी के पास राज्य स्तर पर कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं है. स्मृति ईरानी इस खालीपन को बखूबी भर सकती हैं. दूसरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयानों का आक्रामक जवाब देने में स्मृति हमेशा सबसे आगे रही हैं. 2027 में जब कांग्रेस और सपा सीधे चुनाव लड़ने के मूड में हैं तो स्मृति की मौजूदगी बीजेपी के लिए डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग रोल तय करेगी.